EDITORIAL

GST And Telecom

The Goods and Services Tax Regime after much discussion and debates has given its birth pangs on the midnight session of July first of this year. It is funny to see the efforts of the present Government to equate the event as one that of August 15th 1947, midnight session of Indian Independence which one is unparallel and incomparable to any event in the history of India. It is easy for any reader of Telecom to know the basics of GST Laws and Rules by doing Google search. Our attempt here is to focus the impact of GST on our Telecom Sector.

After liberalization policies, Indian telecom has attained its unique core place to drive our economy. Telecom trade in India is beyond anybody's imagination and reaching even 3 lakh crores in service area itself. Manufacturing sector has its own GDP contribution. Telecom trade is directly as well indirectly linked to enhance our GDP growth.

The main argument that pushed GST into practice is "GST one of the greatest Indirect Tax Reforms to unify multitude of indirect taxes and bring all goods and services under a single GST. It will boost economic growth and improve the ease of doing of business by allowing seamless flow of Goods and transactions at state borders without any barriers."

Many economists and Finance Ministers of earlier regime exposed the fallacies in the argument. There is no uniform rate and it varies from 5 % to 28 % and has its own Central GST, State GST and Inter-state GST. Regarding telecom, major players have brought to the knowledge of Government some of their main concerns on the advent of GST and pleaded the Government not to increase the tax from 15%.

The GST council, a committee headed by Finance Minister Arun Jaitley and comprising representatives of all states which is tasked to fix tax rates on various goods and services, has decided that telecom services will attract tax rate of 18 per cent, three percentage higher than the current 15 per cent services tax. Now it is being levied and shown separately as 9% CGST and 9% SGST. It has its own complications in sector like telecom which one is fully controlled and licensed as a central service

The industry has expressed its apprehension over the higher tax rate saying that it will further stress the already bleeding sector. "Telecom industry hails GST as an iconic reform but we are disappointed with announced rate of 18 per cent….It will augment the existing burden of the industry further. This is also likely slowdown the planned rollout of infrastructure across the country…," said COAI one of the chief stake holders and opinion makers of the Industry. Media is reporting the high and cut throat competitive scenario.

The tariffs for data usage have fallen to rock-bottom levels for all operators whereas voice calls are now free. In the case of postpaid customers, most of them have cut down on their mobile expenses by shifting to lower-priced plans.

TelCos, presently, do not even have any mechanism to track intra-Circle termination and roaming supplies. Issues with regard to pricing of recharge coupons for pre-paid customers are likely to crop-up. Unfortunately, the problem of inadmissibility of credits relating to expenditure on passive infrastructure doesn't seem to have been clearly addressed. This not only vitiates the seamless flow of credit, one of the hallmark principles of GST regime, but also triggers a fresh round of litigation for the sector. For Telecom equipment and service provider, there are problems like 'composite supply' needs to be addressed.

One of the biggest impact areas of GST is the compliance requirements that the tax reform brings with it. As against a single registration and merely two-three returns, the proposed legislation would require TelCos to file manifold returns per year, apart from separate assessments and audits in each of the States. Besides, the new regime may open a Pandora's Box relating to taxability of SIM cards, recharge coupons etc. Our staff in BSNL is reporting us the voluminous work involved in these changes on account of GST.

Prepaid vouchers, etc. are sold by telcos

through a distribution channel consisting of a large number of distributors and retailers. Given the distribution chain involved in the sale of recharge vouchers, the location where prepayment is received for recharge vouchers could be different from the location where such recharge voucher is sold. This problem is to be addressed.

Telecom is not only voice and data and it is now banking services like mobile valet. The GST indirect tax implication is not clear in the mobile valet services. Power and fuel comprise 10% of the total expense in the telecom. We do not know the impact of the same on Telcos and especially on BSNL

The above mentioned are some of the concerns expressed by the Telcos for doing the business smooth under the changed tax regime namely GST. We hope that BSNL might have expressed all its concerns about the impact of GST on our financial viability and expansion of business. It is better, if BSNL gives a proper analytical report about the impact after experiencing the GST in the financial quarter July-September 2017 to make us all aware of the same.

The Minister is reporting that he will not approach GST council immediately for the problems. Our main concern is about our Customers and their increased expenditure to avail services because of higher tax rates and impact on Business of BSNL.

संपादकीय

दूरसंचार सेवा पर वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव

शासन ने विस्तृत चर्चा एवं वार्तालाप के उपरान्त इस वर्ष के पहली जुलाई की मध्यरात्रि में आहूत सत्र की वेदना के साथ वस्तु एवं सेवा कर का जन्म दिया। यह हास्यापद प्रतीत हुआ कि वर्तमान सरकार ने 15 अगस्त 1947 के भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के लिए आहूत मध्यरात्री सत्र के समान इसे महिमामंदित करने का प्रयास किया, जबकि भारत की आजादी हेतु आहूत मध्यरात्रिय शम भारतीय इतिहास में अतुलनीय तथा असमानान्तर है। गुगल पर खोज करने पर "टेलीकॉम" के पाठक जी.एस.टी. के आधारभूत विधि एवं नियम से अवगत हो सकते हैं। यहां दूरसंचार सेवा नर जी.एस.टी. के प्रभाव को उजागर करने का हमने प्रयास किया है।

उदारीकरण के दौर में भारतीय दूरसंचार सेवा ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एक अद्‌भुद आयाम तक पहुंचाया है। भारतीय दूरसंचार सेवा किसी के सोच से परे तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक का सेवा प्रदत्त व्यापार हैं एवं दूरसंचार सेवा प्रत्यक्ष अध्रवा परोक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी) की वृद्धि से जुड़ी हुई है।

जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के संबंध में भारी – भरकम तर्क यह है कि यह महानतम प्रत्यक्ष टैक्स है जो विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का विलम कर एकल जी. एस.टी. में समाहित करती हैं।

इससे आर्थिक विकास को बस मिलेगा तथा राज्य सीमाओं पर वस्तु का आवागमन अवाध रूप से होगा।

अनेकों अर्थशास्त्री एवं पूर्व वित्तमंत्रियों ने जी.एस.टी. के खामियों का पर्दाफास किया है। इसमें एक रूपता नहीं है और यह पांच प्रतिशत से अठ्ठाइस प्रतिशत तक चलते हुए, केन्द्रीय जी.एस.टी., राज्य जी.एस.टी. एवं अन्तर्राज्यीय जी. एस.टी. में बंटती है। अतः एक राष्ट्र और एक टैक्स की बात सच नहीं लगती। सेवा क्षेत्र के प्रमुख संचालाकों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए दूरसंचार सेवा पर जी.एस.टी. पन्द्रह प्रतिशत से नहीं बढ़ाने का आग्रह किया था।

श्री अरूण जेटली वित्तमंत्री की प्रधानता में गठित जी.एस. टी कौंसिल जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, दूरसंचार सेवा पर पूर्व के पन्द्रह प्रतिशत के उपर तीन प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए अठारह प्रतिशत जी.एस.टी. की अनुशंसा की जो लागू भी हो गया है। इसकी वसूली नौ प्रतिशत राज्य जी. एस.टी. एवं नौ प्रतिशत केन्द्र जी.एस.टी. के नाम हो रही है। दूरसंचार सेवा पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित है अतः इस प्रकार के हिस्सेदारी से अलग तरह का प्रभाव हो सकता है।

दूरसंचार सेवा के जानेमाने हिस्सेदार एवं नीति निर्धारक सी.ओ.ए.आई ने कहा कि यह रक्त व मन करते हुए दूरसंचार क्षेत्र पर कड़ा प्रहार है और उससे दूरसंचार सेवा परिचालन पर भारी दवाब बनेगा तथा राष्ट्रीय संसाधन सिमटने की बाध्यता होगी। मिडिया में उच्च एवं गालाघोंट प्रतिस्पर्धा इसका कारण बताया जा रहा है।

सभी दूरसंचार परिचालकों के लिए डाटा सेवा का दर न्यूनतम बिंदु पर है तथा वायस काल वस्तुतः फ्री कर दिया है। इस हालात में पोसट पेड कस्टमर कम रेट दर पर अपनी सेवा बदल रहे हैं।

दूरसंचार सेवा परिचालकों को वर्तमान में अन्तरसर्किस रोमिंग तथा टर्मिनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री पेड ग्राहकों के रिचार्ज कपून की कीमत में बढ़ोत्तरी होगी। संसाधानों पर खर्च किये गये लगत की उगाही का कोई सुनिश्चित स्थिति दृष्टिगत नहीं हो रहा है। यह उधार की स्थिति को वृद्धि करेगा और अड़चनें पैदा होगी।

जी.एस.टी. को महत्ता में शामिल टैक्स सुधार की बात कही कई है। इससे दूरसंचार संचालकों को राज्य वार बहुत तरह की वित्तीय आकलन से बचने की बात है तथा ऑडिट में सुविधा की बात कहीं जा रही है। परन्तु बीएसएनएल में कार्यरत कर्मियों का अनुभव यह बता रहा है कि सीम कार्ड, बीजा, रीचार्ज कूपन तथा विभिन्न पैकेज सेवाओं की बृहत गणना एवं कर का आकलन कार्य का बोझ बढ़ा रहा है जो

कर्मचारियों की घटती संख्या में और भी मुश्किल होगी।

बीएसएनएल में प्री–पेड वाउचर खुदरा विक्रेताओं की कड़ी से बिक्री की जाती है जी.एस.टी से बाउचर की बिक्री और रिचार्ज दो स्थानों पर हो सकते हें, यहां पर टैक्स की गणना जटिल होगी।

दूरसंचार क्षेत्र केवल वायस एवं डाटा तक सीमित नहीं है अब यह मोबाईल बैलट के मार्फत बैंकिंग सेवा से भी जुड़ गई है। जी.एस.टी. का अप्रत्यक्ष कर प्रभाव मोबाइल बैलेट के लिए स्पष्ट नहीं की गई है। बिजली एवं ईधन का दूरसंचार सेवा पर दस प्रतिशत लागत होती है पता नहीं है कि जी. एस.टी. के अवतरण के वाद इसका प्रतिशत क्या होगा?

उपर्युक्त कुछ तथ्य जी.एस.टी. के बाद टेलीकाम सेवाओं को सुगमता से संचालित करने की दिशा में चिन्ता पैदा करती है जिन्हें दूर करना होगा। आशा है बी.एस.एन.एल. प्रबंधन हमारे परिचालन और विकास पर जी.एस.टी. के प्रभाव के विषय में सरकार से अलग कराया होगा।

अगर जुलाई–सितम्बर वित्तीय तिमाही के तहत जी.एस. टी. से प्रभावित वित्तीय स्थिति को आकलन से हमें अवगत कराया जाता तो यह सराहनीय कदम होगी।

मंत्री महोदय का कहना है कि दिक्कतों के लिए वे जी. एस.टी. कौंसिल से तुरंत इत्तला नहीं करेंगे। हमारी मुख्य चिन्ता बी.एस.एन.एल के ग्राहकों पर जी.एस.टी. के कारण बढ़ती बोझ के पीछे हमारी जीवंतता एवं विकास के बाधित होने के विषय में है। आइये हम एकजुट प्रयास से बीएसएनएल के सुदृढ़ करें।